अमर उजाला

नई दिल्ली । शुक्रवार, 15 मार्च 2019

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया है...
-हिलेरी क्लिंटन

अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री

मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में चीन ने चौथी बार अड़ंगा लगाकर एक बार फिर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख दिखाया है। इसके बावजूद भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने कूटनीतिक प्रयास और तेज करने चाहिए।

चीन का अड़ंगा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगाकर आतंकवाद के खिलाफ अभियान को धक्का पहुंचाया है। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद के दो अन्य स्थायी सदस्यों अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के 1267 आईएस और अल कायदा प्रतिबंध समिति की सूची में शामिल किए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले एक दशक के दौरान चीन तीन बार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को लटका चुका है। दरअसल 62 अरब डॉलर के निवेश से बनाए जा रहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरना है, लिहाजा यह माना जा रहा है कि चीन अपने मित्र पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता। चीन ने यह कदम तब उठाया है, जब भारत ने पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर की संलिप्तता के सुबूत पाकिस्तान सहित अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को मुहैया कराए हैं। ध्यान रहे, पुलवामा हमले की चीन ने भी निंदा की थी, लेकिन जब बात मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की आई, तो उसने पैंतरा बदल लिया। एक धारणा यह भी है कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन भारत का इस पर रुख एकदम स्पष्ट है कि वह जम्मू-कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेगा और पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी हो सकती है, जब वह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। यह दुखद है कि आतंकवाद के मुद्दे को राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमले के लिए चुनावी मुद्दे में बदल दिया है। जबकि इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि भारत को दीर्घकालीन रणनीति पर विचार करना चाहिए। सुरक्षा परिषद में अब छह महीने बाद ही अगला प्रस्ताव आ सकता है और चीन को तीन महीने का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। यही ठीक समय है, जब भारत को चीन को राजी करने के साथ ही सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था में सुधार के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए।

पाकिस्तानी महिलाओं का आंदोलन

भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कगार से पीछे हटते ही दोनों मुल्कों के उच्चायुक्त अपने-अपने काम में लग गए और करतारपुर कॉरिडोर पर वार्ता के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं। इससे यह लगने लगा है कि इस उपमहाद्वीप में हालात सामान्य हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिछले हफ्ते पाकिस्तान में महिलाओं ने 'औरत मार्च' निकाला, जिसकी अब भी चर्चा हो रही है। हमने वर्षों से देखा है कि भारतीय महिलाएं कितनी मुखर और गतिशील हैं और उन्होंने विशेष रूप से बलात्कार के खिलाफ अंतहीन विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया है, क्योंकि बलात्कार की घटनाएं भारत में बढ़ गई हैं।

हालांकि पाकिस्तान की महिलाएं भी यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हैं, लेकिन अब भी वे समलैंगिक अधिकारों के लिए आगे नहीं आई हैं, जिसके लिए हाल में भारत में पुरुषों और महिलाओं को आंदोलन करते देखा गया। पाकिस्तान न केवल एक संकीर्ण समाज है, बल्कि समलैंगिकता इस्लाम में भी प्रतिबंधित है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सांसद कृष्णा कुमारी कोहली को सम्मान देते हुए सीनेट के अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर बैठाकर उस दिन के सत्र का संचालन करने के लिए कहा। कृष्णा कुमारी कोहली पहली हिंदू दलित और दूसरी हिंदू महिला हैं, जिन्हें यह सम्मान दिया गया। वह महिला अधिकारों और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने अभियानों के लिए जानी जाती हैं।

इससे ठीक पहले पंजाब मंत्रिमंडल के सूचना मंत्री फैय्याजुल चौहान को प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण पद से हटा दिया। पूरे पाकिस्तान ने एकजुट होकर उन्हें

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत अनेक शहरों में हजारों महिलाओं ने इकट्ठा होकर पितृसत्ता के खिलाफ नारे लगाए और अपने हकों की बात की।

मरिआना बाबर, पाकिस्तानी पत्रकार

हटाने की मांग की और यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों, जैसे मानवाधिकार मंत्री ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री से मांग की कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में यह एक स्वस्थ नया बदलाव है, जहां धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता दिखाई जा रही है।

इस बीच कराची, लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, लरकाना और पाकिस्तान के अन्य नगरों में हजारों महिलाओं ने 'हम औरतें' बैनर के तले इकट्ठा होकर पितृसत्ता के खिलाफ नारे लगाए और मुल्क में महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली यातनाओं और सामाजिक विकास व अन्य क्षेत्रों में उनके योगदान पर बातें कीं। यह देखना दिलचस्प था कि इस वर्ष ट्रांसजेंडर भी 'औरत मार्च' में शामिल होने आए थे। सरकार धीरे-धीरे समाज में इन ट्रांसजेंडरों को शामिल कर रही है और उन्हें विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं।

'औरत मार्च' का उद्देश्य पूरे पाकिस्तान की महिलाओं के साथ एकजुटता जताना और कार्यस्थल पर, घर में, सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के हाथों हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ जवाबदेही और सशक्त न्याय के लिए दबाव बनाना था। 'औरत मार्च' में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने श्रम अधिकारों को लागू करने के साथ आर्थिक न्याय की मांग की और अन्य चिंताओं को भी उठाया, जैसे स्वच्छ पेयजल, हवा, वन्यजीवों और अन्य जानवरों की सुरक्षा, खाद्य और नकदी फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को मान्यता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली तक पहुंच, प्रजनन न्याय, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच, शैक्षणिक संस्थानों में समावेशन, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार, युद्ध विरोधी एजेंडे को बढ़ावा और पुलिस बर्बरता और जबरन गायब करने की घटनाओं का अंत।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद शेरी रहमान ने 'औरत मार्च' को संबोधित करते हुए महिलाओं के कई मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, 'मैं इसलिए इस मार्च में शामिल हुई हूं, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और अवसर नहीं मिलते, क्योंकि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए मुझे अश्लील चुटकुलों पर चुप रहने के लिए कहा जाता है। मैं अपनी उन अभागी बहनों के लिए इस मार्च में शामिल हुई हूं, जो रोज अपमान झेलती हैं।'

यहां तक कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा तक ने पाकिस्तानी महिलाओं को संदेश भेजने और उन्हें शुक्रिया कहने के लिए समय निकाला। उन्होंने वर्दी में काम करने वाली, घर पर रहने वाली महिलाओं और विशेष रूप से शहीदों की विधवाओं के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान की प्रगति में इस मुल्क की महान महिलाओं की भूमिका और जवाबदेही है।

जैसी कि अपेक्षा थी, कुछ पुरुषों द्वारा इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया जताई गई, जो मानते हैं कि ये महिलाएं वैसे अधिकार मांग रही हैं, जो संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इस संस्कृति ने ही उन्हें आवाज उठाने वाली महिलाओं की ऑनर किलिंग की इजाजत दी है। वे यह भूल जाते हैं कि कोई भी मजहब और संस्कृति ऑनर किलिंग की इजाजत नहीं देती। फिर हमारे यहां खासकर पख्तूनों में एक क्रूर संस्कृति भी है, जिसमें विवाह में महिलाओं की अदला-बदली होती है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है, तो उसकी बहन को उसके भाई से शादी करनी होती है और उसकी बहन से उसकी राय भी नहीं पूछी जाती। पाकिस्तान ने दुनिया की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को देखा है, लेकिन राजनीति में आने के लिए आम पाकिस्तानी महिलाओं के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं।

पाकिस्तानी महिलाओं के सामने एक अन्य मुद्दा यह है कि शहरी केंद्रों में कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, इस प्रकार वे कई आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित रहती हैं। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में महिला कार्यबल की भागीदारी मात्र 24 फीसदी है।

इस वर्ष 'औरत मार्च' में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं, जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, पर उन्होंने बीती सदी के अस्सी के दशक में पाकिस्तान में नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जब उन्होंने सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिनका महिलाओं के खिलाफ बहुत क्रूर कानून था। लेकिन तमाम प्रगति के बावजूद आज भी इसे एक सहकारी आंदोलन में बदलने के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है, जो वास्तव में पाकिस्तान में सामाजिक व राजनीतिक बदलाव को बढ़ावा दे सके।

अंतर्ध्वनि

>> सरदार पूर्ण सिंह

सोने और चांदी से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता

आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपये है; परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ-सौ बिकते हैं! सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए, तो फिर स्वर्गप्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य-पूजा ही सच्ची ईश्वर-पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना कुछ ही कहो - आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है-यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला-कौशल के विचार और चिंतन किस काम के! सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर-चिंतन, अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला-कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर-प्रप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं, जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सबके सब प्रेम-शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन-शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे-बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है।

-मशहूर दिवंगत साहित्यकार

मंजिलें और भी हैं

>> उद्धव भराली

इंजीनियर नहीं बन पाया पर नई खोज जारी है

जब मैं अपने गांव में कबाड़ से लोहा-लक्कड़ निकालकर कुछ बनाने की कोशिश करता था, तब लोग मुझ पर हंसते और मुझे पागल कहते थे। कुछ पढ़े-लिखे, शिक्षित लोग मेरे पास आकर खड़े हो जाते और बेकार का काम छोड़कर मुझे कुछ सार्थक करने के लिए कहते। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं, उसे ये लोग बेकार का काम क्यों समझ रहे हैं। लेकिन अच्छा यह हुआ कि गांव के लोगों की टोकाटोकी से बेपरवाह मैं अपने काम में लगा रहा। उसी का नतीजा था कि मैं पॉलिथीन थैली बनाने की मशीन तैयार कर पाया। वह 1988 की बात थी। उसकी भी एक अलग कहानी है। मैं असम के जिस लखीमपुर जिले का रहने वाला हूं, वहां उस समय चाय के अलावा और कोई उद्योग नहीं था। चाय उद्योग को पैकिंग के लिए भारी मात्रा में पॉलिथीन थैलियों की जरूरत पड़ती थी। हमारे यहां पॉलिथीन थैली बनाने का कोई उद्योग नहीं था। मैंने तब 67,000 रुपये में पॉलिथीन थैली तैयार करने की मशीन बनाई, जिसे स्थानीय स्तर पर बहुत सराहा गया। अभी तक मैं करीब डेढ़ सौ नई चीजें बना चुका हूं। नवाचार भरी इसी सोच के कारण मुझे पद्मश्री सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं।

मुझे सबसे ज्यादा प्रशंसा तब मिली, जब मैंने अनार छीलकर दाने निकालने की मशीन का आविष्कार किया।

लेकिन मेरा बचपन इतना सुखद नहीं था। मैं बहुत मेधावी छात्र था। बहुत छोटी उम्र में ही मुझे नई-नई चीजें बनाने का शौक था और मैं इंजीनियर बनना चाहता था। पर हमारी पारिवारिक स्थिति अचानक खराब हो गई, तो पिता द्वारा लिया गया भारी कर्ज चुकाने के लिए मुझे कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब मुझे अनेक छोटे-मोटे काम करने पड़े। लेकिन तब भी नई खोज का मेरा उत्साह थोड़ा भी कम नहीं हुआ। बल्कि पॉलिथीन थैली मशीन बनाने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैं दरअसल जुगाड़ के जरिये बड़ी मशीनों का सस्ता विकल्प तैयार करने के प्रति ज्यादा उत्सुक था, जो टिकाऊ भी हो और कुशल भी। कुछ समय बाद मैं एक नौकरी पर अरुणाचल प्रदेश चला गया। लेकिन तीन साल बड़े भाई की असमय मृत्यु के बाद मुझे लखीमपुर लौटना पड़ा, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी।

अगले दस साल तक घर पर रहकर मैंने कुल चौबीस उत्पाद बनाए, जो खेती में किसानों की मदद के लिए थे। इसमें लहसुन से लेकर गन्ना छीलने वाली मशीनें हैं, तो चाय पत्ती कटर भी है। इन खोजों की भी एक वजह है। दरअसल बड़ी-बड़ी कंपनियां ज्यादातर बड़े उद्योगों के लिए काम करती हैं। बड़ी कंपनियां खेती और किसानों की बेहतरी के बारे में नहीं सोचतीं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रशंसा तब मिली, जब 2006 में मैंने अनार छीलकर उसके दाने निकालने की एक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की खासियत यह है कि छिलका हटाने के क्रम में अनारदानों को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचता। इस खोज ने मेरी पहचान बना दी और नेशनल इनोवेशन सेंटर, अहमदाबाद ने इसका संज्ञान लिया। यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेरी इस खोज की चर्चा हुई। काम, पहचान और पैसा हो जाने के बावजूद मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। हाल ही में मैंने लखीमपुर में गरीबों के लिए एक शेल्टर होम शुरू किया, जहां भोजन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा निःशक्तजनों की बेहतरी के लिए भी मैं कुछ काम कर रहा हूं। जिस पृष्ठभूमि में मैं निकलकर आया हूं, उसमें कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

चुनाव के लिए किसानों का एजेंडा

जवानों की तरह किसान भी देश की सेवा करते हैं और हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। क्या किसान देश की जो सेवा करते हैं, वह राष्ट्रवाद के दायरे में नहीं आता? यह चुनाव एक बड़ा अवसर है, जब किसानों की भी आवाज सुनी जाए।

यह चुनाव का समय है। ऐसे में हमें अगले पांच वर्ष का राष्ट्रीय एजेंडा स्पष्ट करने की जरूरत है। हम सब खुद को कृषि पर निर्भर समाज कहते हैं, और खेती पर देश की 130 करोड़ जनता का भोजन निर्भर है। मगर नई पीढ़ी की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह आकर्षण खो रही है। किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाने तक के लिए कर्ज लेना पड़ता है। नौकरियां न होने से उनके बच्चे गहरी हताशा में हैं। हम सबको मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त हताशा को दूर करने पर विचार करना चाहिए। हम सबको मिलकर इसके लिए राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैंने विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर पांच प्रस्ताव सुझाएं हैं, ताकि कृषि क्षेत्र को संकट से उबारा जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ वोट में है। ये पांच प्रस्ताव हैं-

पूर्ण कर्जमाफी : शहरी मतदाता सोचते हैं कि कर्जमाफी करदाताओं के धन की बर्बादी है और कर्ज माफी से किसान बेपरवाह हो जाएंगे और सरकारों से कर्जमाफी की उम्मीद करेंगे। हकीकत यह है कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कम रखती है, ताकि लोगों को सस्ते में अनाज मिल सके, जबकि खेती की लागत बढ़ती जा रही है। सरकारी एजेंसियां बहुत कम खरीद करती हैं और किसानों को खुले में सस्ते में फसल बेचनी पड़ती है। इन्हीं वजहों से किसान कर्ज में डूबते हैं और खुदकुशी करने को मजबूर होते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) : किसान समय पर कर्ज की किस्त चुका सकें और भविष्य में कर्ज के

वी एम सिंह

लिए निर्भर न हों, इसके लिए एमएसपी का निर्धारण सी-2 के अनुसार हो, जिसमें पारिवारिक श्रम, जमीन का किराया और ब्याज को लागत में जोड़ा जाता है।

सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि फसल एमएसपी से कम में न बिके। यानी न्यूनतम का मतलब न्यूनतम ही हो और इससे कम में खरीद करने वालों को दंडित करने का प्रावधान हो।

फसल बीमा : चूंकि किसान कर्ज व्यक्तिगत स्तर पर लेते हैं, इसलिए बीमा दावे के लिए फसल के नुकसान का आकलन भी पूरे गांव के आधार पर नहीं, बल्कि किसानों को हुए व्यक्तिगत नुकसान के आधार पर हो। प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसान की स्थिति में कर्ज में उसी अनुपात में छूट मिले।

किसान पेंशन : पचास साल से अधिक समय से देश में *जय जवान, जय किसान* का नारा लग रहा है। जवानों को बीस वर्ष तक सेवा करने के बाद पेंशन मिलती है। इसी तरह से किसानों के लिए भी 20 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

गन्ना किसानों को भुगतान : तीन करोड़ गन्ना किसान परिवारों के लिए बकाए का भुगतान न होना दशकों से एक बड़ी चिंता का कारण है। वैधानिक रूप से 14 दिनों में भुगतान होना चाहिए, लेकिन किसानों के बरसों के संघर्ष के बावजूद यह नहीं हो सका है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सरकार को भुगतान में देरी की स्थिति में 15 फीसदी का ब्याज लगा देना चाहिए। मिलों को बैंकों से 12 से 13 फीसदी की दर पर ब्याज मिलता है। जब उन्हें 15 फीसदी की दर से ब्याज देना पड़ेगा तो वह भुगतान नहीं रोकेंगी। आगामी चुनाव में इस पांच सूत्री एजेंडा को क्यों नहीं अपनाया जा सकता? पुलवामा में हुए आतंकी हमले के कारण 2019 में राष्ट्रवाद केंद्रीय मुद्दा बन गया है। क्या किसान देश की जो सेवा करते हैं, वह राष्ट्रवाद के दायरे में नहीं आता? यह चुनाव एक बड़ा अवसर है, जब किसानों की भी आवाज सुनी जाए।

-लेखक, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक हैं

हरियाली और रास्ता

राहुल, मेहना और चाय

एक चाय दुकान, जहां से मेहना को समझ में आया कि गरीब भी इज्जत के साथ कैसे चाय पी सकते हैं।

राहुल और मेहना कंपनी की तरफ से दो दिन के लिए मुंबई गए थे। मुंबई पहुंचने पर दोनों ने अपनी मीटिंग खत्म की और सैर पर निकल पड़े। गिरगांव चौपाटी से मरीन ड्राइव होते हुए वे दोनों गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। थोड़ी देर वहां समय बिताकर वे पास के चाय हाउस में गए। सुहाना मौसम, समुद्र का किनारा और गर्मागर्म चाय। तभी मेहना की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो मर्सिडीज से उतरा और चाय हाउस में आकर बैठ गया। वेटर ऑर्डर लेने पहुंचा, तो वह बोला, एक मसाला कटिंग मुझे, और एक टेबल पर। मेहना को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर में वेटर एक आधी कप चाय और एक दफ्ती का स्टैंड लेकर आया, जिस पर लिखा था-एक मसाला कटिंग। उस शख्स ने चाय पी और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद भिखारी जैसा दिखने वाला एक गरीब आदमी वहां आया और उसी मर्सिडीज वाले शख्स की जगह बैठ गया। वेटर आया, तो उस आदमी ने वेटर को वही दफ्ती वाला स्टैंड पकड़ा दिया। वेटर कुछ देर में उसके लिए आधा कप चाय ले आया। वहीं पास वाली टेबल पर चार लड़के बैठे थे। जब वेटर उनसे ऑर्डर लेने गया, तो वे बोले, चार स्पेशल और एक टेबल पर। इस बार मेहना सब कुछ समझ गई। उसे यह आइडिया अच्छा लगा। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? मेहना बोली, वह जो आदमी दिखाई दे रहा है, उसके पास शायद चाय पीने के पैसे भी न हों। पर यहां उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। वह इज्जत से अपनी चाय पी रहा है। और होटल को भी इससे कोई नुकसान नहीं। है न बेहतरीन सोच! राहुल थोड़ा चकराते हुए बोला, कोई मुफ्त चाय पिए और होटल को भी कोई नुकसान न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मेहना ने वेटर को इशारा किया और बोली, दो स्पेशल और एक टेबल पर।

यदि समर्थ लोग थोड़ी संवेदना दिखाएं, तो गरीब भी इज्जत से जी सकते हैं।

खुली खिड़की

मोबाइल इंटरनेट की औसत रफ्तार

मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के मामले में आइसलैंड दुनिया में सबसे अव्वल है, उसके बाद नॉर्वे और कतर का स्थान आता है। लेकिन हमारे देश में मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार बहुत धीमी (9.9 एमबीपीएस) है, और दुनिया में इसका स्थान 111वां है।

स्रोत-SpeedTest

जीवन की कसौटियां

एक दिन चाणक्य का एक परिचित उनके पास आकर बहुत उत्साह के साथ कहने लगा, आप जानते हैं कि अभी-अभी मैंने आपके मित्र के बारे में क्या सुना है? चाणक्य अपनी तर्कशक्ति, ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए विख्यात थे। उन्होंने उस परिचित की सूचना पर बहुत अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सामने वाले से पूछा, मेरे मित्र के बारे में आप जो कुछ भी कहने वाले हैं, क्या वह सत्य है? और क्या इस बारे में आपको पूरी जानकारी है? यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा मुरझा गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह सच ही है। बल्कि मैंने इस बारे में कहीं सुना था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि आपके मित्र के बारे में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह पूरी तरह सच ही है। चाणक्य ने दोबारा उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप मेरे मित्र की कोई अच्छाई बताने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, उस आदमी ने कहा। चाणक्य ने कहा, यानी आप मेरे मित्र के बारे में जो भी कहना चाहते हैं, वह न सत्य है और न ही अच्छा है। ठीक है, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। क्या मेरे मित्र से संबंधित उस जानकारी की मेरे लिए कोई उपयोगिता है? उस आदमी ने कहा, नहीं, उपयोगिता तो नहीं है, हां इससे आपको उनके बारे में पता चलता। अब चाणक्य ने कहा, फिर मुझे वह बात नहीं सुननी है, रहने दीजिए।

सत्संग

-संकलित